इकाई 4 जनता की क्रांतिकारी कार्रवाई

इकाई की रूपरेखा

4.0 उद्देश्य

इस इकाई में हम फ्रांसीसी क्रांति के उद्भव और क्रांति काल की महत्वपूर्ण विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप यह समझ पाएंगे कि :

- किस प्रकार आर्थिक संकट ने क्रांति की स्थितियां बनाई,
- वे कौन से मुद्दे थे जिन पर शहरी तथा ग्रामीण शक्तियों को लामबंद किया गया,
- एक विचारधारा को प्रस्तुत करने में दार्शनिकों की क्या भूमिका रही,
- जनता की भागीदारी ने किस प्रकार क्रांतिकारी संघर्ष की दिशा बदल दी,
- राष्ट्रीय असेम्बली ने क्या लोकतांत्रिक उपाय लागू किए और उनका नतीजा क्या हुआ,
- पुरानी व्यवस्था ध्वस्त होने के बाद क्रांतिकारी सरकार ने वैधीकरण के सिद्धांतों को कैसे लागू किया, और
- वह किस प्रकार का राजनीतिक संघर्ष था जिसने फ्रांस की राजनीतिक पार्टियों को जन्म दिया।

4.1 प्रस्तावना

फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस को राजनीतिक संस्कृति का अगुआ बना दिया था। फ्रांस ने न केवल राजनीति तथा लोकतंत्र के ऐसे नए सिद्धांतों को स्थापित किया जो बाद में काफी समय तक यूरोपीय विचार को प्रभावित करते रहे, अपितु उसने क्रांतिकारी कार्रवाई की एक नई शब्दावली भी प्रदान की। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के क्रांतिकारी सिद्धांत आज भी पूरे विश्व के लोकतांत्रिक समाजों में विशिष्ट स्थान रखते हैं।

यह समझने के लिए कि वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके परिणामस्वरूप फ्रांस में राजतंत्रीय सरकार के साथ–साथ सामंतवादी व्यवस्था भी पूरी तौर पर ध्वस्त हो गई हमें क्रांति का समर्थन

अथवा विरोध करने वाले विविध सामाजिक हित समूहों की पृष्ठभूमि की संक्षिप्त जानकारी लेनी होगी। क्रांति के प्रत्यक्ष कारणों का अध्ययन करने के अतिरिक्त, यह जानना भी आवश्यक है कि निर्णायक क्षणों में आम आदमी के हस्तक्षेप ने किस प्रकार न केवल क्रांति को विफल होने से बचा लिया, अपितु इसकी दिशा को भी प्रभावित किया। थर्ड इस्टेट की लोकतांत्रिक कार्रवाई ने वैधता का नया सिद्धांत स्थापित किया। 1792 में जनता की सीधी कार्रवाई ने क्रांति को एक लोकतांत्रिक गणतंत्र की दिशा में आगे बढ़ाया और क्रांतिकारी विचारधारा तथा राजनीति ने एक अपरिपक्व स्वरूप वाले राजनीतिक दलों के गठन का मार्ग प्रशस्त किया।

4.2 प्राचीन शासन का क्रांतिकारी तख्ता पलट तथा लोकतांत्रिक कार्रवाई

आगे के उप–अनुच्छेदों में आपको उन शक्तियों के विषय में बताया जाएगा जिन्होंने फ्रांस में क्रांतिकारी परिवर्तन की जमीन तैयार की।

4.2.1 आर्थिक संकट और जन असंतोष

अठारहवीं शताब्दी के अधिकांश वर्षों में फ्रांस की अर्थव्यवस्था औसत वृद्धि और संपन्नता वाली रही। किंतु इसके फल सबको समान रूप से नहीं मिले। तेल उद्योग, सूती निर्माताओं, बड़े बंदरगाहों, चीनी मिलों तथा औपनिवेशिक वाणिज्य का तो स्पष्ट विस्तार हुआ। 1771–72 के वर्षों में फसल खराब हो जाने के कारण अनाज तथा रोटी की कीमतों में अनिवार्य वृद्धि हुई, जिसके चलते अनेक स्थानों पर असंतोष की स्थिति पैदा हो गई। प्राचीन शासन व्यवस्था का वास्तविक आर्थिक संकट 1775 से शुरू हुआ। शराब का आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो जाने के कारण कीमतें गिरने लगीं और मुनाफा कम हो गया। शराब के धंधे में मंदी का दौर सात–आठ साल तक चला। इसके बाद चारे का भीषण अभाव हो गया ओर उसने कितने ही पशुओं की जानें ले लीं। इस संकट ने फ्रांस की लगभग एक–तिहाई आबादी को प्रभावित किया। 1787 से भयंकर बर्फीले तूफानों, जबरदस्त ठंड और सूखे के बाद अनाज का एक बड़ा संकट शुरू हुआ। अनाज तथा रोटी की कीमतें डेढ़ से दो गुनी तक बढ़ गई। ग्रामीण संकट के दुष्प्रभाव औद्योगिक क्षेत्र पर भी पड़े, जहां बिक्री घटने लगी और इसके कारण उत्पादन में कमी हुई तथा बेरोजगारी की समस्या पैदा हो गई। 1786 की फ्रांसीसी ब्रिटिश संधि ने फ्रांसीसी मजदूरों के सामने संकट खड़ा कर दिया क्योंकि फ्रांस में आने वाले ब्रिटिश उत्पादों पर से आयात शुल्क कम कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि फ्रांस के अनेक शहरों, विशेषकर पेरिस, में जनता में असंतोष फैल गया और वहां रोटी को लेकर दंगे हुए। उस दौरान निकले उत्तेजक परचों ने जिन अफवाहों और अटकलों का बाजार गरम किया उससे लोगों के मन भय और क्रोध से भर उठे।

देहाती इलाकों में, राजकीय करों तथा दशमांश के थोपे जाने की किसानों में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। उनका गुस्सा भी बुर्जुआ एजेंटों के विरूद्ध भड़का जिन्होंने जंगलों में मवेशियों को चराने के समान अधिकारों के खिलाफ नियम बना दिए और साझा जमीनों के सिद्धांत का विरोध किया। इसी को देखते हुए जॅर्ज लफेव्र ने यह निष्कर्ष निकाला कि किसान क्रांति सामंत–विरोधी (नए जमींदारों द्वारा साझा जमीनों को हड़पे जाने के विरूद्ध) थी। इस प्रकार आर्थिक संकट तथा राजनीतिक घटनाओं की छत्रछाया में किसान आंदोलन आगे बढ़ा।

4.2.2 राज्य के वित्तीय ढांचे का टूटना और राजनीतिक संकट

सरकार अपने अनावश्यक खर्चों के जाल से निकल नहीं पाई और कराधान की दोषपूर्ण व्यवस्था ने वित्तीय ढांचे के टूटने की स्थिति ला दी। वित्तीय घाटा 1120 लाख लीव्र हो गया, सरकार की साख खत्म हो गई और फ्रांस राष्ट्रीय दिवालियापन की स्थिति में जा पहुंचा। अमीर तथा पुरोहित वर्ग को मिली वित्तीय छूट के कारण आक्रोश की स्थिति बन गई थी। महावित्त नियंत्रक कालॉन ने कर ढांचे को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की। इसके लिए उसने एक नई अनुक्रमिक कर व्यवस्था को रूप दिया जिसमें कुलीनजनों को प्राप्त वित्तीय विशेषाधिकारों की जड़ें खोखली करने का पूरा इंतजाम था; किंतु कालॉन की यह कोशिश सफल नहीं हुई। उसके पास सीमित विकल्प था। वह स्वीकृति के लिए पेरिस की संसद पर निर्भर नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे इसके सदस्यों की ओर से प्रचंड

विरोध की अपेक्षा थी। राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा, अर्थात इस्टेट जनरल को बुलाने का मतलब था सरकारी दिवालियापन को स्वीकार करना, और इस स्थिति में तेज कार्रवाई कठिन हो जाती। इसलिए कालॉन ने विशिष्टजन (नोटेबल) सभा को बुलाने की सिफारिश की।

4.2.3 संसद तथा विशिष्ट जनों का विद्रोह

विशिष्ट जन सभा (असेम्बली ऑफ नोटेबल्स) की बैठक पेरिस के निकट अवस्थित शाही महल वेरसाय में 22 फरवरी, 1787 को हुई। सभा के सदस्यों ने कालॉन के वित्तीय प्रस्तावों पर जमकर प्रहार किए और सुधारों को बड़े बेहुदे ढंग से खारिज कर दिया गया। विशिष्ट जन सभा की बैठक को फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कहा जा सकता है। कुलीन जन भी शाही सरकार की बढ़ती शक्ति से अप्रसन्न थे। विशिष्ट जनों ने यह घोषणा कर दी कि नए कर लगाने के किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी देना उनके अधिकार से बाहर की बात थी। एक प्रमुख विशिष्ट जन लाफायेत ने तो यह तर्क दिया कि केवल एक सच्ची राष्ट्रीय असेम्बली ही कर व्यवस्था में किसी प्रबल सुधार को स्वीकृति दे सकती है और ऐसी असेम्बली इस्टेट जनरल ही थी, जिसकी बैठक 1614 के बाद से हुई ही नहीं थी।

कालॉन के उत्तराधिकारी ब्रीएन ने सितम्बर 1787 में सुधारों के एक उदार कार्यक्रम को पेरिस की संसद के माध्यम से लागू करने का प्रयास किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। सरकार की ओर से वित्तीय आदेशों को पारित करने में हुई देरी के कारण पेरिस की संसद में विरोधी गुटों को अपनी शक्ति को संगठित करने का अवसर मिल गया। स्टाम्प ड्यूटी और भूमि कर के प्रस्तावों को रद्द कर दिया गया। जनता का समर्थन पाने के उद्देश्य से अनेक पर्चे भी बांटे गए, जिनमें यह प्रचारित किया था कि संसद केंद्र सरकार की निरंकुशता से जनाधिकारों की रक्षा कर रही थी। इसका परिणाम यह हुआ कि पेरिस में सरकार के खिलाफ, ब्रितनी में शाही लोक सेवकों (सिविल सर्वेन्ट्स) के खिलाफ और दोफीने में शाही सैनिकों के खिलाफ कुछ दंगे हुए। एक बार फिर महा नियंत्रक बना दिए गए नेकर के पास सुधारों को मंजूरी देने के लिए इस्टेट जेनरल की बैठक बुलाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहा।

4.2.4 इस्टेट जेनरल का आहवान और क्रांति की शुरुआत

कुलीन जन और केंद्र की निरंकुशता के बीच चलने वाला टकराव जल्दी ही विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग तथा विशेषाधिकार वंचित वर्ग के बीच टकराव में बदल गया जब सरकार ने इस्टेट जेनरल की बैठक बुलाई। 1788 में, फ्रांसीसी सरकार ने 4.5 अरब लीवर का ऋण लिया, और सम्राट लूई सोलहवें को इस्टेट जेनरल सभा से अतिरिक्त धन लेने को बाध्य होना पड़ा, क्योंकि परम्परा से ही सम्राट के लिए नए कर मंजूर कराने का अधिकार इस्टेट जेनरल के पास ही था। इस्टेट जेनरल में तीन वर्ग थे जो फ्रांसीसी समाज के तीन अंगों का प्रतिनिधित्व करते थे। इन अंगों को इस्टेट कहा जाता था। प्रथम वर्ग में रोमन कैथोलिक पुरोहित आते थे, द्वितीय वर्ग में अमीर लोग आते थे और तृतीय वर्ग (थर्ड इस्टेट) में फ्रांसीसी समाज के वे जनसाधारण आते थे जिन पर समूचे करों का बोझ होता था। किंतु तीसरे वर्ग के अन्तर्गत व्यवसाय, शिक्षा तथा संपदा के मामले में भारी भिन्नताएं थीं। प्रत्येक वर्ग के लिए अलग चुनाव होते थे और मतदाता अपने प्रतिनिधियों के लिए अपनी शिकायतों की सूची तैयार करते थे। इन्हें शिकायतों के रजिस्टर कहा जाता था। अमीर वर्ग के शिकायती रजिस्टरों में जहां सामंती अधिकारों तथा विशेषाधिकारों वाली उनकी पुराने समय से चली आ रही स्वतंत्रता की मान्यता पर जोर दिया जाता था, वहीं मध्य वित्त वर्ग के शिकायती रजिस्टरों को अधिकतर उदारवादी व्यवसायों के लोग लिखते थे जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा एक लिखित संविधान की मांग उठाते थे। वे यह निश्चित करना चाहते थे कि कानून के समक्ष सब बराबर हों तथा सभी वर्गों पर करों का बोझ बराबर डाला जाए।

जनता को एकजुट करने का काम केवल आर्थिक संकट अथवा राजनीतिक मुद्दों ने नहीं किया। मुख्य समस्या तो फ्रांसीसी समाज में बढ़ते अन्तर्विरोध थे। कुछ मुट्ठी भर जनता पर करों तथा वित्त इकट्ठा करने के लिए समूचा बोझ लादा जा रहा था और उन्हें सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ रहा था। किंतु मध्यम अथवा बुर्जुआ वर्ग ने संपदा अथवा सामाजिक हैसियत दोनों ही दृष्टि से अपने आपको लगातार ऊपर उठाया, और इस तरह पुराने समय से चली आ रही व्यवस्था को चुनौती दे डाली। नेतृत्व समाज के इसी वर्ग से निकला और जनसाधारण क्रांतिकारी सुधार की संभावना को देखकर हरकत में आ गए। इन लोगों ने मिल जुल कर तृतीय वर्ग की स्थापना की।

इस्टेट् जेनरल की बैठक 5 मई, 1789 को हुई और सरकार की ओर से कोई दृढ़ नेतृत्व न होने के कारण मामलों ने तुरंत तूल पकड़ ली। सरकार ने तृतीय वर्ग की सीटें दोगुनी कर दी थीं क्योंकि यह वर्ग समाज के सर्वाधिक आबादी वाले तबके का प्रतिनिधित्व करता था। तृतीय वर्ग ने यह सुझाव रखा कि तीनों वर्ग अलग–अलग वोट करने की वजाय एक व्यक्ति एक वोट के आधार पर एक निकाय के रूप में इकट्ठे वोट करें। पुरोहित वर्ग के कुछ सदस्य तो आम जन के साथ किसी समझ पर पहुंचने को तैयार थे, किंतु अमीर वर्ग ने इन विचारों को ही खारिज कर दिया और एक अड़ियल रूख अपना लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि आम जन ने बहिष्कार कर दिया और स्वयं को जनता का असली प्रतिनिधि बताते हुए 17 जून, 1789 को अपने आपको 'राष्ट्रीय असेम्बली' चुन लिया। उन्होंने फ्रांस के लिए एक संविधान तैयार करने और कानून के समक्ष बराबरी की स्थिति बनाने का फैसला किया, इस प्रकार वे एक स्वेच्छाचारी सरकार के स्थान पर जनता की प्रभुसत्ता के प्रबोधन (इनलाइटेनमेंट) आंदोलन के विचारों को ही परिलक्षित कर रहे थे, जिनकी हिमायत ऐबे सेये ने अपने प्रसिद्ध परचे ''तृतीय इस्टेट क्या है' ? में की थी। इस समय तक क्रांति का नेतृत्व कोई सुगठित दल या आंदोलन के हाथों में नहीं था, अपितु इसका नेतृत्व एक सुसंबद्ध सामाजिक गुट के अंदर उभरने वाले विचारों में आम सहमति के आधार पर हो रहा था जिसने क्रांतिकारी संघर्ष को प्रभावकारी एकता भी प्रदान की। यह गुट वकीलों, डाक्टरों, लेखकों, नोटरी तथा अधिकारी जैसे पेशेवर लोगों का उदारवादी बुर्जुआ वर्ग था। ये लोग दार्शनिकों तथा अर्थवेत्ताओं के बनाए क्लासिकल उदारवाद तथा प्रबोधन आंदोलन के विचारों से भली प्रकार परिचित थे।

टेनिस कोर्ट शपथ

राष्ट्रीय असेम्बली, यह विचारते हुए कि इसे राज्य का संविधान स्थापित करने, सार्वजनिक व्यवस्था को पुनर्निर्मित करने, तथा राजतंत्र के सच्चे सिद्धांतों को बनाए रखने हेतु बुलाया गया है; कि इसे जिस स्थान में भी स्वयं को स्थापित करने हेतु बाध्य किया जा सकता है, वहां अपने विचार विमर्शो को जारी रखने से इसे कोई भी नहीं रोक सकता; और, अंत में, यह कि जहां कहीं भी इसके सदस्य जमा होते हैं, वहीं राष्ट्रीय असेम्बली का अस्तित्व होगा।

यह आदेश दिया जाता है कि इस सभा के सभी सदस्य तुरंत यह गंभीर शपथ लेंगे कि जब तक राज्य का संविधान स्थापित नहीं हो जाता तथा दृढ़ आधार पर जम नहीं जाता, वे अलग नहीं होंगे और जहां कहीं भी परिस्थितियों की मांग होगी वे पुनः जमा होंगे ....

'ए डाक्यूमेंट्री सर्वे ऑव दि फ्रेंच रिवोल्यूशन', जॉन हॉल स्टूअर्ट संपा (न्यू यार्कः मैकमिलन, 1951), पृ. 88

4.2.5 दार्शनिकों की भूमिका

फ्रांसीसी क्रांति के समय यदि दार्शनिकों के विचारों और उनके नए-नए शब्दों की उपस्थिति नहीं होती तो शायद यह क्रांति एक शासन के स्थान पर दूसरा शासन आने और एक नई व्यवस्था का प्रारंभ होने की घटना मात्र बन कर रह जाती। इतिहासकारों ने फ्रांसीसी क्रांति को गति देने में दार्शनिकों की भूमिका पर बहस की है। 1789 और 1848 के बीच के वर्षो में चिंतन तथा कर्म का एक महत्वपूर्ण सूत्र रूसो के 1762 के 'सामाजिक अनुबंध' (सोशल कांट्रैक्ट) ने दिया, जिसमें उसने लिखा था 'मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र होता है किंतु हर कहीं उस पर बंधन होते हैं'। रूसो ने विशेषकर तथा अठारहवीं शताब्दी के प्रबोधन के दर्शन ने यह शिक्षा दी कि मनुष्य जाति की प्रगति तब होगी जब उन रूढ़िवादी व्यवस्थाओं को चुनौती दी जाएगी जो अनेक लोगों की कीमत पर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाती है। प्रबोधन धारा के चिंतकों का यह मानना था कि प्रगति का अर्थ व्यक्तिगत आत्म-अभिव्यक्ति का विकास और जन्म, सामंती विशेषाधिकार तथा श्रेणी विनियमों (गिल्ड रेगुलेशंस) पर आधारित प्राधिकार की समाप्ति होता है। दार्शनिकों ने हालांकि क्रांति की वकालत नहीं की, तदापि उन्होंने उभरते बुर्जुआ वर्ग तथा समूचे राष्ट्र के हाथों में क्रांतिकारी संघर्ष में असरदार हथियार का काम करने वाले कुछ ऐसे शब्द थमा दिए जिनमें क्रांति का संकेत निहित था जैसेः सितॉयां (नागरिक), ल्वा (कानून), पैत्रई (गृहभूमि) आदि। रूसो की जनता की 'प्रभुसत्ता' तथा 'आम इच्छा' की अवधारणा ने नेताओं को यह सोचने पर बाध्य कर दिया कि समाज को समग्र रूप में अपने स्वयं के हित तय करने चाहिए। इन विचारों का प्रसार राजनीतिक बहसों, क्लबों, अतिथि गृहों तथा शैक्षिक संस्थाओं के जन आंदोलन के सा संबंध बनाने के माध्यम से हुआ।

शिक्षित अभिजात्य वर्ग तक प्रबोधन के विचारों का फैलना एक महत्वपूर्ण कदम था, किंतु उतनी ही महत्वपूर्ण सैलूनों तथा क्लबों की भूमिका भी थी। सैलून तो धनी शहरी अभिजात्य लोगों की शानदार बैठकें थीं जहां दार्शनिक तथा अतिथि गण एकत्र होते थे और प्रायः नए विचारों को लेकर बौद्धिक चर्चाएं किया करते थे। क्रांति के प्रारंभिक दौर में सैलून और क्लब तो मीराबो, बारनाव, रौबेसप्यार, पेत्यौं, द्यूपार तथा सेयेस जैसे सुधारवाद प्रेमियों के लिए मेल–जोल के केंद्र बन गए।

4.2.6 प्राचीन शासन के क्रांतिकारी तख्ता पलट में जनता की भूमिका

तृतीय इस्टेट को अपनी बैठक के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक कक्ष एक इनडोर टेनिस कोर्ट के रूप में मिला, जहां उसके सदस्य 20 जून को एकत्र हुए। तभी से बाजी राजा के हाथ से निकल चली थी। सम्राट ने अपने सर्वाधिक लोकप्रिय मंत्री नेकर को बरखास्त करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और लगभग 20,000 सैनिकों को बुलाकर उन्हें पेरिस-वेरसाय क्षेत्र में मोर्चाबंदी पर लगा दिया। मीराबू के भाषण ने जनता का ध्यान बंटा दिया और वह हिंसा पर उतर आई। इस्टेट् जेनरल के चुनावों ने परचों तथा पोस्टरों के माध्यम से राजनीतिक माहौल को पहले गरमा दिया था। पेरिस के आम जन ने (जिनमें पेरिस के एक दरिद्र मोहल्ले सेंट अंटोनी तथा फाबू के किराएदार, मजदूर, मिस्तरी, दुकानों में काम करने वाले, यहां तक कि छोटे दुकानदार भी शामिल थे) ने इसका जवाब 14 जुलाई 1789 को बैस्टील पर हमला करके दिया। बैस्टील एक प्रमुख कारागार दुर्ग तथा शाही शस्त्रालय था, जो पेरिस के मध्य में अवस्थित था। बैस्टील के पतन को फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत माना जाता है। इसके राजनीतिक परिणाम भी उल्लेखनीय रहे। राष्ट्रीय असेम्बली न केवल बच गई, अपितु उसे सम्राट की भी मान्यता मिल गई। पेरिस में सत्ता निर्वाचक समिति के हाथों में चली गई जिसने एक नगर परिषद (पेरिस कम्यून) का गठन कर दिया। सम्राट को बाध्य होकर लाफायेत को राष्ट्रीय गारद (नेशनल गार्ड) नामक नागरिक सेना का सेनापति नियुक्त करना पड़ा।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेरिस की घटनाओं के प्रभाव तथा कठिन आर्थिक स्थितियों ने परेशानियां खड़ी कर दीं। जुलाई 1789 के अंत तथा अगस्त 1789 के प्रारंभ के महा भय (ग्रेट फियर) के नाम से विख्यात ग्रामीण अंचल के विस्तार में फैलने वाली जन आतंक की लहर और प्रांतीय कसबों के आंदोलन ने मिलकर किसान अशांति को एक बड़े विप्लव का रूप दिया। यह अफवाह उड़ी कि अमीर लोग तीसरी इस्टेट को गिरा कर सत्ता हथियाना चाहते हैं और इस षडयंत्र में उन्होंने अनाज के सटोरियों तथा जमाखोरों के साथ हाथ मिला लिया और वे लोगों को भूखा मारने पर उतारू हैं जिससे लोग उनके आगे घुटने टेक दें। इस अफवाह का परिणाम यह हुआ कि लोगों ने स्थानीय सहायक नागरिक सेना अथवा 'किसान गारद' बनाकर अपने आपको हथियारबंद करना शुरू कर दिया। किसान अपने भूपतियों पर हमला करने लगे, अमीरों की हवेलियां जलाने लगे, सामंतों के दस्तावेजों को नष्ट करने लगे और उन्होंने कर तथा दशमांश देने से भी इनकार कर दिया। किसानों को शांत करने और व्यवस्था बहाल करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय असेम्बली ने सामंती शासन तथा सामंती विशेषाधिकारों तथा पुरानी सामाजिक–राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा कर दी। उसका दूसरा बड़ा काम था 'मनुष्य के अधिकारों की घोषणा' (स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की घोषणा); और यही घोषणा स्वतंत्रता का घोषणापत्र बन गया। इसने शाही प्रजा को फ्रांस का नागरिक बना दिया और उन्हें कानूनी बराबरी भी दे दी। इस प्रकार राजनीति को आकार देने का काम असेम्बली से बाहर के दबावों ने किया तो उसके भीतर के राजनीतिज्ञों ने भी।

मनुष्य के अधिकारों की घोषणा 27 अगस्त, 1789

1) मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं और उनके अधिकार भी समान होते हैं; सामाजिक विभेदों का आधार केवल सामान्य उपयोगिता हो सकती है।

2) प्रत्येक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य होता है मनुष्य के नैसर्गिक तथा अहरणीय अधिकारों का संरक्षण; ये अधिकार हैं स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा, तथा अत्याचार का प्रतिरोध

3) समस्त प्रभुसत्ता का स्रोत मूल रूप में राष्ट्र में निहित होता है; कोई भी समूह, कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी प्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता जो राष्ट्र प्रदत्त न हो

4) कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है; समस्त नागरिकों का यह अधिकार है कि वे व्यक्तिगत रूप में अथवा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में योगदान करें; कानून सभी के लिए समान होना चाहिए, चाहे यह रक्षा करे या दंड दे। सभी नागरिक

कानून के समक्ष समान हैं, इसलिए सभी को यह छूट है कि वे अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी सार्वजनिक पद, पदवी तथा रोजगार ग्रहण कर सकते हैं, और गुणों तथा प्रतिभा के अतिरिक्त अन्य किसी भी आधार पर उनमें भेद नहीं किया जा सकता।

5) किसी को भी उसके विचारों के कारण चुप नहीं कराया जा सकता; धार्मिक विचारों के कारण भी नहीं, जब तक कि उनकी अभिव्यक्ति से कानून द्वारा सीमित सार्वजनिक व्यवस्था के भंग होने का खतरा न हो।

6) विचारों तथा मतों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति मनुष्य का एक सर्वाधिक मूल्यवान अधिकार है। परिणामस्वरूप, प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने तथा छापने को स्वतंत्र है, किंतु कानून के आधार पर इस प्रकार की स्वतंत्रता के दुरूपयोग का उत्तरदायित्व उसी का होगा ....

'ए डाक्यूमेंट्री सर्वे ऑफ दि फ्रेंच रिवोल्यूशन', जॉन हॉल स्टूअर्ट द्वारा संपा. (न्यू यार्क: मैकमिलन, 1951), पृ. 114

लूई सोलहवां इस पूरे समय में वेरसाय में निष्क्रिय रहा। उसने सामंतवाद की समाप्ति तथा मनुष्य के अधिकारों की घोषणा से संबंधित आदेश को लागू करने से इनकार कर दिया। क्रांति अभी भी सुरक्षित नहीं थी, और उसकी उपलब्धियों के लिए अक्टूबर 1789 में एक बार फिर लड़ाई लड़ी गई। रोटी की भारी किल्लत, लूई के बचाव के लिए फ्लैंडर्ज रेजीमेंट का आगमन और राष्ट्रीय असेम्बली के प्रति लूई की उदासीनता की यह परिणति हुई कि क्रांति में स्त्रियां भी सक्रिय रूप में शामिल हो गईं, और हजारों की संख्या में, वे लोग वेरसाय की ओर चल पड़े। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार "हर दिशा से औरतों की टोलियां झाड़ू, तलवारों, पिस्तौलों और बंदूकों से लैस होकर आईं, और उनके पीछे–पीछे लोगों की भीड़ आई, और लाफायेत के नेतृत्व में 20,000 पेरिस गार्ड भी आए। उन्होंने सम्राट और उसके परिवार को पेरिस में स्थित शाही महल त्वेलरी में शरण लेने को विवश कर दिया। जब सम्राट ने पेरिस में खाद्यान्न की तुरंत आपूर्ति करने और राष्ट्रीय असेम्बली के फैसलों को मान लेने का वायदा कर लिया तो भीड़ खुशियां मनाते हुए उसके आगे–आगे चिल्लाती हुई चली 'बेकर, बेकर की बीबी, और बेकर का लड़का' (जिससे उनका आशय निश्चय ही सम्राट, महारानी और उनके उत्तराधिकारी से था, जिसे फ्रांस में 'दोफँ' कहा जाता था)।

अक्टूबर 1789 से 1795 तक स्त्रियों ने अनेक तरीकों से क्रांति में भागीदारी की। ऑलैंप द गूजे स्त्रियों के राजनीतिक अधिकारों का प्रमुख प्रवक्ता बन गया। उन्होंने पुरुषों के साथ बराबरी की मांग की। उन्होंने रोटी तथा मूल्य नियंत्रण के लिए प्रदर्शन किए और अपनी 'पितृभूमि' की रक्षा में हिस्सा लिया। साबुन की कीमतें बढ़ीं और हजारों औरतों पर इसका असर पड़ा तो स्त्रियों ने साबुन दंगों की अगुआई भी की। मजदूर औरतों का संगठन 'क्रांतिकारी गणतंत्रवादी महिला समाज' क्रांति की शुरुआती दौर में बेहद सक्रिय रहा जब तक कि उसका दमन नहीं कर दिया गया। 'आतंक' के दौर में स्त्रियों ने इस कारण से क्रांति का विरोध किया क्योंकि इससे पारिवारिक जीवन को, धर्म संस्था (चर्च) को और उपभोक्ता सामग्री की आपूर्ति को नुकसान पहुंचता था। लेकिन उस समय के पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों की मांगों को अधिक गंभीरता से नहीं लिया गया।

क्रांति के शुरुआती दौर में, राष्ट्रीय असेम्बली ने राजनीतिक ढांचे को सुधार कर उसे संवैधानिक राजतंत्र का रूप देने के अपने प्रयासों को जारी रखा, किंतु दो घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने 1791 के बाद क्रांति की दिशा ही बदल दी। पहली घटना धर्म से संबंधित थी। धर्म संस्था (चर्च) को एक विशेषाधिकार प्राप्त व्यवस्था तथा सामंतवादी शासन के समर्थक के रूप में देखा जाता था। दशमांश की समाप्ति के बाद चर्च की तमाम सम्पत्ति और जमीन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और उन्हें बिक्री के लिए खोल दिया गया। 'पुरोहित वर्ग के नागरिक संविधान' (12 जुलाई, 1790) के अनुसार, बिशप तथा पुरोहितों का चुनाव जनता के वोट से होना तय हुआ और पुरोहितों को ऐसे वेतनभोगी सरकारी अधिकारी बना दिया गया जिन्हें संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेना अनिवार्य था। केवल 54 प्रतिशत पल्ली पुरोहितों ने यह शपथ ली जबकि अधिकांश बिशपों ने इसे लेने से इंकार कर दिया। इसका अर्थ हुआ राष्ट्रीय एकता के दौर का अंत। इससे गृह युद्ध की स्थितियां पैदा हो गई, क्योंकि पादरी विरोधी मुददे ने राष्ट्र को नए आधारों पर बांट कर रख दिया। इस मुददे ने कट्टर कैथोलिकों, राजतंत्र समर्थकों, प्रवासियों आदि की क्रांति विरोधी शक्तियों को फिर से एकजुट कर दिया। दूसरी घटना थी सम्राट का पलायन करके उन प्रवासियों से हाथ मिलाना जिन्होंने विदेशी ताकतों की मदद से क्रांतिकारियों को हराने की कोशिश की। इस प्रकार राजतंत्र जनता का समर्थन

पूर्ण रूप से खो बैठा। फ्रांस 1792 में एक गणतंत्र घोषित हो गया और लूई सोलहवें पर मुकदमा चला कर जनवरी 1793 में उसे मौत की सजा दे दी गई।
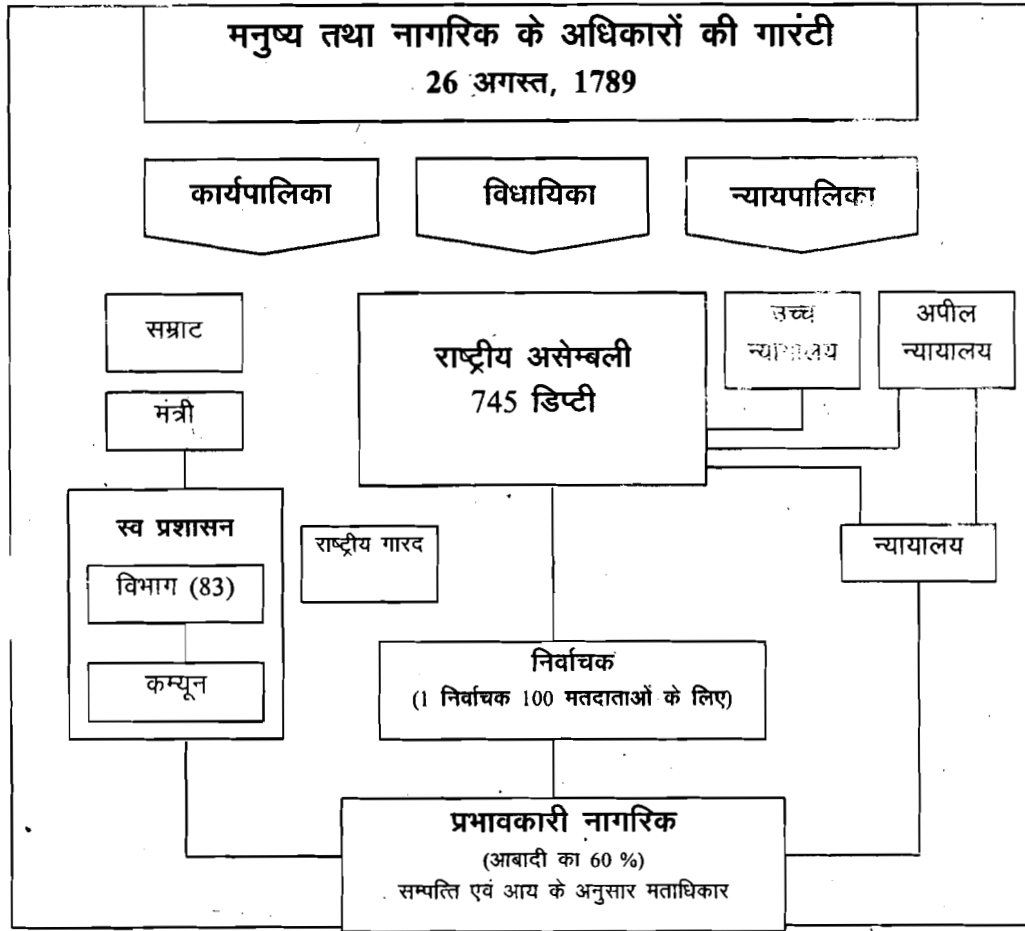
बोध प्रश्न 1

1) किसानों की प्रमुख आर्थिक शिकायतें क्या थीं ? 100 शब्दों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

2) आर्थिक सुधार के प्रस्ताव क्यों असफल हो गए ? 60 शब्दों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

3) फ्रांसीसी समाज के विभिन्न विभाजनों तथा तृतीय इस्टेट की समस्याओं की व्याख्या कीजिए। 100 शब्दों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

4) फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की क्या भूमिका रही ? 100 शब्दों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

4.3 वैधीकरण के सिद्धांत

फ्रांसीसी क्रांति पर हाल में जो लिखा गया है उससे यह संकेत मिलता है कि क्रांति की जड़ें उस राजनीतिक संस्कृति में थीं जिसने प्राचीन शासन के अंतिम वर्षों में आकार लिया। निरंकुश शासन तथा प्रबोधन की राजनीति में जो अंतर्विरोध रहे उन्होंने ही इस संकट को जन्म दिया। निरंकुश राजतंत्र को जिस समाज के अंतर्गत काम करना था, इसका राजनीतिक संस्कृति के प्रगतिशील सिद्धांतों के साथ गहरा अंतर्विरोध था। इस नई संस्कृति ने एक क्रांतिकारी संवाद का आधार उपलब्ध किया तथा वैधता का मुद्दा उठाया।

डेनिस रीशे, गेनिफी जैसे अनेक इतिहासकारों ने इस बात का उल्लेख किया है कि तृतीय इस्टेट ने अपने आपको राष्ट्रीय असेम्बली का रूप देने के लिए 17 जून, 1789 को जिस प्रस्ताव को मतों के आधार पर पारित किया, वह सबसे पहला तथा सबसे गहन कार्य था। इसमें क्रांतिकारी सरकार के लिए वैधता के नए सिद्धांत निहित थे। तृतीय इस्टेट की महत्ता पर जोर स्येस ने ही दिया था। स्येस ने दो क्रांतिकारी सिद्धांत रखेः राष्ट्र की एक मात्र तृतीय इस्टेट के साथ पहचान बनाना और यह दावा कि केवल राष्ट्र को ही फ्रांस का संविधान देने का अधिकार था। मई और अगस्त 1789 के बीच समूचा प्राचीन शासन ही ध्वस्त हो गया। फ्रांसीसियों ने अपने राष्ट्रीय अतीत को अस्वीकार कर क्रांति के सिद्धांतों को चुन लिया था। जब राष्ट्रीय असेम्बली ने सामंती विशेषाधिकारों को समाप्त कर फ्रांस के भावी संविधान को तैयार करने का बीड़ा उठाया तो वह संविधान सभा बन गई। 4 तथा 11 अगस्त की राजाज्ञाओं ने तमाम व्यक्तिगत विशेषाधिकारों, दासता तथा दशमांश को समाप्त कर दिया और सभी के लिए मुफ्त तथा समान न्याय और रोजगार की स्वतंत्रता की स्थिति बनाई। इस प्रकार, फ्रांस में एक नया कानूनी समाज स्थापित हो चुका था।

संविधान सभा की दो बहसें वैधता के सिद्धांतों की दृष्टि से निर्णायक रहीं। ये थीं : (क) मनुष्य के अधिकारों की घोषणा, तथा (ख) संप्रभुता का विषय। सामंती शासन को समाप्त करके, संविधान सभा ने फ्रांसीसी जनता को ऐसे व्यक्तियों के रूप में नई परिभाषा दी थी जो स्वतंत्र और समान थे। जो बुनियादी अधिकार तय किए गए, उनमें कुछ थे स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा तथा अत्याचार का प्रतिरोध। संक्षेप में, फ्रांसीसी शासक की प्रजा को राष्ट्र का नागरिक बना दिया गया। मनुष्य के अधिकारों की घोषणा ने समाज की एक क्रांतिकारी अवधारणा सामने रखी, और नए सरकारी अधिकारियों को संगठित किया कि वे क्रांतिकारी सिद्धांतों पर आधारित एक लिखित संविधान के माध्यम से इन अधिकारों की रक्षा करें।

सितम्बर में शुरू होने वाली दूसरी बहस संप्रभुता की प्रकृति तथा आरोपण के सवाल को लेकर थी। 'संप्रभुतासम्पन्न' का मुद्दा असाधारण रूप से कठिन साबित हुआ। वर्गों तथा विशेषाधिकारों पर आधारित समाज के ध्वंस ने प्रतिनिधित्व के एक नए मुद्दे को उठा दिया। नेताओं की समझ में यह आ गया कि राष्ट्र की संप्रभुता को राष्ट्र के सभी नागरिकों द्वारा इसके अधिकारों को प्रत्यक्ष उपयोग के अनुकूल बनाना असंभव था। स्येस ने ही नई संस्थाओं की आवश्यकता और लोकतंत्र के दावों के बीच संप्रभुता के प्रयोग की समस्या का एक तर्कसंगत समाधान प्रस्तुत किया। एकसदनीय असेम्बली ऐसी एकमात्र जगह बन गई जहां जनता की सामान्य इच्छा व्यक्त हो सकती थी। कुछ लेखक यह तर्क देते हैं कि इस प्रकार की परिभाषाओं की परिणति यह हुई कि राजतंत्र के स्थान पर

राष्ट्रीय असेम्बली की एक नई किस्म की निरंकुशता आ गई। आने वाले वर्षों में, लोकतंत्र की जन आधारित तथा संसदीय अवधारणाओं के बीच एक बुनियादी द्वंद्व की स्थिति बन गई, क्योंकि दोनों का ही दावा अभिन्न संप्रभुता का था।

4.3.1 जैकबिन गणतंत्र और आतंक (1792-94)

लूई सोलहवें ने जून में भागने की कोशिश करके एक संविधान सम्मत सम्राट की हैसियत से फ्रांस पर शासन करने की वैधता और अधिकार खो दिए। उग्र सुधारवादियों (क्रांतिकारियों) ने क्रांति की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कुलीन जन की प्रतिक्रिया के खतरे को हथियार बनाया। उन्होंने अप्रैल 1792 में आस्ट्रिया पर युद्ध की घोषणा कर दी क्योंकि आस्ट्रीआई सम्राट लीओपोल्ड द्वितीय ने पिलनित्स की घोषणा करके फ्रांसीसी सम्राट के सम्पूर्ण अधिकार को यूरोपीय ताकतों की मदद से जबरन बहाल करने की धमकी प्रस्तुत कर दी थी। उग्र सुधारवादियों (क्रांतिकारियों) ने पेरिस के आम लोगों और कॉर्दल्ये (एक क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब) तथा जैकबिन क्लब जैसे अतिवादी राजनीतिक गुटों से समर्थन लिया। उन्होंने सम्राट को गद्दी से उतार दिया और एक नए गणतंत्रवादी संविधान का लिखित प्रारूप तैयार करने के लिए अगस्त सितम्बर 1792 में एक राष्ट्रीय कनवेंशन का गठन किया। इसका चुनाव सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार के आधार पर किया गया।

जैकबिन क्लब के सदस्यों और जन आंदोलन (विशेषकर पेरिस कम्यून के 'सांकूलॉत') के बीच जो गठबंधन हुआ उसने 'स्वतंत्रता' के शत्रुओं के विरूद्ध रॉबेसप्यार के नेतृत्व में क्रांतिकारी तानाशाही के लिए एक अनिवार्य बुनियाद तैयार कर दी। पेरिस के लोकप्रिय उग्रवादियों ने 1792 के बाद कुछ सुसंगत विचारों तथा व्यव्हारों को एक सही दिशा प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप एक प्रत्यक्ष सरकार तथा जनप्रिय लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह संस्था स्येस तथा मारा की सुझाई केंद्रीकृत तानाशाही से भिन्न थी। जनता की संप्रभुता को संपूर्ण मानते हुए, पेरिसवासियों ने स्वायत्ता के सिद्धांतों, कानूनों को स्वीकृत करने तथा निर्वाचित अधिकारों को नियंत्रित करने एवं वापस बुलाने के अधिकार को अपना लिया। इस प्रकार जैकबिन तानाशाही के आधार प्रतिनिधिक लोकतंत्र का स्थान प्रत्यक्ष लोकतंत्र ने ले लिया। चुनाव का स्थान नियुक्ति ने ले लिया। यहां क्रांतिकारी समितियों का उद्‌विकास महत्वपूर्ण है – सर्वाधिक शक्तिशाली समिति थी जन सुरक्षा समिति। इसको समस्त अधिकार मिले हुए थे और यह स्वयं को 'सामान्य इच्छा' के प्रतिनिधि के रूप में पेश करती थी और यह कनवेंशन की सर्वाधिक शक्तिशाली कार्यकारी समिति बन गई। इसने 'जनरल मैक्सिमम' के कानून को लागू किया। पेरिस के क्रांतिकारी मजदूर वर्ग की मांग पर बने इस कानून में खाद्य तथा पेय से लेकर ईंधन तथा वस्त्र तक की कीमतों पर नियंत्रण लगाया गया। स्वतंत्रता और गणतंत्र के शत्रुओं के प्रति जो युद्धोन्मुख होने की स्थिति बनी उस कारण नेता लोगों ने आतंक के शासनकाल (जनवरी से जुलाई 1794 तक) की स्थापाना की। इस दौर में सम्राट, रानी, उनके गुप्त समर्थक, कट्टर कैथोलिक, अन्य सटोरिए समेत 40,000 से भी अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। रॉबेसप्यार को अत्याचारी तथा तानाशाह के साथ–साथ लोकतंत्र का संत भी माना जाता है जिसने समाजवाद का रास्ता दिखाया। क्रांतिकारी सरकार का जल्दी ही जनता से सम्पर्क टूट गया और उसका स्वभाव भी तानाशाहीपूर्ण हो गया और रॉबेसप्यार की भी सरकार पर पकड़ ढीली हो गई।

थर्मदॉरी प्रतिक्रिया

राबेसप्यार को मौत के घाट उतारे जाने के बाद के दो दिनों में, लगभग साठ व्यक्तियों वाले समूचे पेरिस कम्यून को क्रांति स्थल से डेढ़ घंटे से भी कम समय में खत्म कर दिया गया और हालांकि मैं मृत्यु दंड स्थल से सौ कदम से भी अधिक दूरी पर खड़ा था, फिर भी मृतकों का खून मेरे पांवों के नीचे बह रहा था। मुझे जिस बात ने चकित किया वह यह थी कि जैसे ही कोई सिर धड़ से अलग होकर गिरता था लोगों के मुंह से 'अ ब ली मैक्सीमम' कानून के बारे में ही आवाज निकलती थी। वास्तव में इस कानून को लागू करने में इतनी अधिक कठोरता बरती गई कि सभी तरह के सामान पर कुछ निश्चित कीमतें निर्धारित कर दी गई और इसके तले आम जनता को अभावों में पिसना पड़ा। और, इसके लिए दोषी ठहराया गया रॉबसेप्यार को। अब जिन लोगों को कष्ट उठाना पड़ रहा था वे सभी अलग–अलग व्यवसाय के थे; और उनमें से अनेक ने तो वास्तव में उस कानून का फायदा उठाया, उसका दुरूपयोग किया था। उन्होंने किसानों को तथा पेरिस के बाजार में सामान देने वाले अन्य व्यापारियों को इस बात के लिए बाध्य किया था कि वे अधिकतम कीमत पर अपना माल बेंचे, और उन लोगों ने उन्हें मनमाने दामों पर खुदरा माल बेचा जो उसे खरीदने की औकात

रखते थे। मैंने रॉबेसप्यार को गुइलोटिन पर जाते हुए नहीं देखा; किंतु मुझे लोगों ने बताया है कि वह उस अवसर पर जिस गाड़ी में वहां से निकला था उसके साथ चलने वाले लोगों ने गाड़ी के अंदर अपने छाते घुसेड़ कर उसके शरीर में घोंपे थे ......अब लोगों के लिए अपने आपको बचाने का यह उपाय बन गया था कि वे यह ऐलान करते थे कि उन्हें रॉबेसप्यार के आतंक के दौर में जेल हुई थी। अब तो जैकबिनों की वेशभूषा मे निकलना भी खतरनाक हो गया था, क्योंकि 'युवा पेरिसवासी' गुट ने कई व्यक्तियों को पेरिस की गलियों में मात्र इसलिए मार डाला था क्योंकि वे लंबे कोट और छोटे बाल धारण किए हुए थे।

'इंगलिश विटनेस ऑफ दि फ्रेंच रिवोल्यूएशन' से जे.ए. टॉमसन द्वारा संपा. (ऑक्सफर्ड· बौसिल ब्लैकवेल, 1938), पृ. 248–49

4.3.2 थर्मोडोरियन गणतंत्र (1795-99)

राबेसप्यार के पतन के बाद तमाम मूलभूत समस्याएं फिर उभर आईं और कनवेंशन में अधिकारों की घोषणा, जनता की संप्रभुता तथा प्रतिनधित्व के सिद्धांत पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई। नई घोषणा में कानून की सर्वोच्चता को सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में लिया गया, किंतु अत्याचार का प्रतिरोध करने (1789) अथवा विद्रोह (1793) के अधिकार गायब हो गए। समानता के अधिकार के साथ 'कर्तव्य' की घोषणा को रखा गया, जिसका लक्ष्य था अधिकारों की असीमित प्रकृति तथा कानून पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता के बीच तनाव को टालना। संप्रभुता के लोकतांत्रिक विचार के अंदर छिपी अपार शक्ति के पिछले अनुभव ने इस विषय पर फिर से चिंतन करने की स्थिति पैदा कर दी। यहां से संप्रभुता की अवधारणा पर विचार विमर्श की एक लंबी परंपरा की शुरुआत हुई जिसके प्रतिनिधि थे बेंजमन कांस्टैंट, मादाम द स्ताल, रवाये–कॉलार तथा गीजो। स्येस ने एक 'संवैधानिक जूरी' बनाकर संप्रभुता पर नियंत्रण लगाने का संकेत दिया। यह जूरी एक विशेष निकाय होला जिसका काम था प्रशासनिक विनियमों तथा कानूनों की संवैधानिकता पर नियंत्रण करना। फ्रांसीसी इतिहास में विधायिका की शक्ति के ऊपर एक न्यायक्षेत्र की श्रेष्ठता की अवधारणा यहां पहली बार दिखाई दी। नए संविधान में एक द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई जिसमें संपत्ति की उच्च योग्यता के आधार पर सामान्य इच्छा का संकोच के साथ पालन करने का प्रावधान था। पांच निदेशकों वाले एक संचालक मंडल का भी प्रस्ताव रखा गया। इसे कार्यपालिका के रूप में काम करना था। व्यवहार में, संचालक मंडल वाले शासन ने फ्रांस, विशेषकर पेरिस, को राजनीति से मुक्त कर दिया। निम्न बुर्जुआ (मध्यम) वर्ग को कोई भी पद लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया, वोटिंग नाम मात्र की रह गई और राजनीति पर धनिकतंत्र तथा पेशेवर प्रशासकों का वर्चस्व हो गया। इस शासन की शक्ति चुनाव के माध्यम से वैधीकरण में नहीं, अपितु पुलिस, सेना तथा नौकरशाही में निहित थी। संचालक मंडल ने विशिष्ट जन के सामाजिक तथा राजनीतिक राज्य की शुरुआत कर दी। विशिष्ट जन का यही वर्ग उन्नीसवीं शताब्दी में हावी रहा।

बोध प्रश्न 2

1) प्राचीन शासन की समाप्ति के बाद वैधीकरण के नए सिद्धांत क्या थे ? 100 शब्दों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

2) थर्मदॉरी गणतंत्र ने किस प्रकार के अधिकार का प्रयोग किया ? 60 शब्दों मे उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

4.4 दलीय राजनीति के वैचारिक विभाजन तथा विभिन्न पहलू

क्रांति के दौर ने अनेक राजनीतिक समितियों को उभरते देखा, जिन्होंने सत्ता के लिए अपनी–अपनी अंदरूनी लड़ाईयां लड़ीं। इनमें सर्वाधिक उल्लेखनीय था कॉर्देल्ये क्लब। इस क्लब का नाम सेन नदी के पास अवस्थित परित्यक्त कॉर्देल्ये मठ के नाम पर पड़ा, जहां इसकी बैठकें होती थीं। इस क्लब का 'सां–कूलॉत' क्रांतिकारियों की गतिविधियों से घनिष्ठ संबंध रहा। ये क्रांतिकारी छोटे–छोटे संपत्ति स्वामी थे जिनमें दस्तकार, दुकानदार और मिस्त्री तथा उग्र विचारों एवं प्रत्यक्ष गणतंत्रवादी लोकतंत्र में आस्था रखने वाले यात्री लोग शामिल थे। यह क्लब पेरिस के आम जन को प्रशिक्षित करके उन्हे एक अत्यधिक प्रभावकारी राजनीतिक शक्ति बनाने में सफल भी रहा। इसी प्रकार जैकबिन क्लब का गठन क्रांति की शुरुआत में ही हो गया था। पहले यह नरमपंथी संगठन रहा और संविधानसम्मत तथा शिक्षित तत्वों को बैठक का स्थान उपलब्ध कराता रहा। किंतु, क्रांति के आगे बढ़ने के साथ यह अधिकाधिक क्रांतिकारी होता गया और इसने पूरे फ्रांस में अपनी शाखाओं का एक मजबूत जाल बनाना शुरु कर दिया। ये क्लब गणतंत्रवाद का एक अड्डा बन गया।

जब नए संविधान के प्रावधानों के अनुसार अक्टूबर 1791 में 745 सदस्यों वाली विधान सभा की बैठक हुई तो सदस्यों में कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था, और वे एक से दूसरे गुट में आते जाते रहे। राजनीतिक दलों के गठन की प्रक्रिया धीमी थी और नियंत्रित पार्टी संगठन का तो अस्तित्व ही नही था। फिर भी, सभा के अनेक सदस्यों में गणतंत्रवाद के विषय में अतिवादी विचार पनपने लगे। ये वही विचार थे जिन्हें जैकबिन तथा कॉर्देल्ये क्लबों ने फैलाया और पोषित किया था। अधिकांश वाचाल गुट सम्राट को हटाने के पक्ष में थे ओर उन्होंने प्रदर्शन की योजना भी बनाई। जुलाई 1791 में चैम्प डी मार्स में प्रदर्शन आयोजित किया गया और लाफायेत के आदेश पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई गई। इन घटनाओं के परिणामस्वरूप विभाजन की स्थिति बन गई, जिसमें लाफायेत तथा राजतंत्र समर्थकों ने जैकबिनों को छोड़ कर फॉयां गुट बना लिया। यह टूटा हुआ गुट नरमपंथी था और संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर था।

4.4.1 संविधानवादी बनाम गणतंत्रवादी

चैम्प डी मार्स मैदान की घटनाओं ने तृतीय इस्टेट के अंदर तेजी से विभाजन किया। सम्राट के साथ समझौता चाहने वालों तथा उसका विरोध करने वालों में एक स्पष्ट विभाजन रेखा खिंच गई। ऐसे बहुत से लोग जो 1789 में राष्ट्रभक्त थे, अब नीचे से बढ़ते दबावों तथा संपत्ति को होने वाले खतरों तथा राजनीतिक नेतृत्व छिन जाने के भय से राजतंत्र तथा फॉयां गुट के समर्थकों की ओर हो गए। बारनाव, द्यूपॉर तथा ईमथ के नेतृत्व में इन नरमपंथियों ने संविधान को राजतंत्र के अधिक अनुकूल बनाने का प्रयास किया। असेम्बली में उनकी संख्या लगभग 260 थी। फॉयां गुट इस बात के लिए तत्पर था कि आम जनता की ओर से मध्यम वर्ग पर कोई खतरा होने से पहले ही क्रांति को समाप्त कर दिया जाए, इसीलिए उन्होंने राजतंत्र और राष्ट्र के सिद्धांतों के बीच मेल–मिलाप कराना चाहा। असेम्बली में संविधान के संशोधन के उनके रूढिवादी अभियान को बहुत कम सफलता मिली।

उनसे संख्या में कम और कहीं अधिक सक्रिय थे जैकबिन क्लब के वामपंथी डिप्टी। उनकी संख्या 140 के आसपास थी। फॉयां गुट की तरह वामपंथी के भी निर्वाचक सभा में अपने समर्थक थे और उनमें दो स्पष्ट राजनीतिक प्रवृत्तियां दिखाई देती थीं।

अतिवादी उग्र क्रांतिकारी भविष्य की रिपब्लिक (गणतंत्रवादी) पार्टी का केंद्रीय अंग बने। ये लोग असेम्बली की अपेक्षा क्लबों में अधिक शक्तिशाली थे। उनके प्रमुख नेता थे मेरलैं द त्यौंबील, शाबो, कूतौं आदि।

वामपंथी डिप्टियों के प्रमुख गुट में ब्रीसो के अनुयायी शामिल थे। विधान सभा में ब्रीसोवादियों के नाम से मशहूर ये लोग राष्ट्रीय कनवेंशन के अधीन जीरोंदियो के रूप में जाने गए – क्योंकि वेरन्यो, ग्रांजनवे, दूको जैसे उनके स्र्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिनिधि ज़ीरोद जिले के थे। जीरोंदी लोग आस्ट्रिया तथा उसके मित्रों के विरूद्ध युद्ध के कट्टर समर्थक थे, जहां से प्रति–क्रांति का खतरा था। उनका

मानना था कि युद्ध से राष्ट्रीय एकता बनेगी। किंतु, लुई सोलहवे और उसके परिवार के पेरिस से भागकर क्रांतिकारियों के साथ मिल जाने से संवैधानिक राजतंत्र का उनका मकसद ही चौपट हो गया। इस घटना के साथ ही फ्रांसीसी राजनीति में फॉयां गुट का आधार खत्म हो गया।

वर्ष 1792 में युद्ध के आगमन ने नरमपंथियों तथा अतिवादियों के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया। इस समय अनाज की कमी, सट्टेबाजी और काला बाजारी तथा प्रति– क्रांतिकारियों के बाहरी खतरों की जो स्थिति बनी उससे लोगों में भय और आतंक गहरा गया। युद्ध ने पेरिस के समाज के निचले तबके को महत्वपूर्ण बना दिया क्योंकि स्वैच्छिक सेनाओं (क्रांतिकारी सेना) का गठन शहरी मजदूर जन में से ही किया गया। इस तरह, युद्ध और आर्थिक कठिनाइयों ने क्रांति का झुकाव वामपंथ की ओर कर दिया। पेरिस में 'सां कूलॉत' ने एकजुट होकर एक शक्तिशाली बल का रूप धारण कर लिया और 10 अगस्त, 1792 को शाही महल त्वेलरी पर आक्रमण कर दिया। इसके फलरूवरूप राजतंत्र का पतन हो गया और फांस एक गणतंत्र बन गया। राष्ट्रीय कनवेंशन की बैठक 20 सितम्बर, 1792 को एक गणतांत्रिक संविधान बनाने के लिए हुई।

4.4.2 जीरोंदी दल के अनुयायियों तथा मानतनयादों के बीच राजनीतिक संघर्ष

राष्ट्रीय कनवेंशन में तीन मुख्य राजनीतिक गुट थे, किंतु यह विभाजन अस्थाई था। बहुमत हालांकि बहुत स्थिर नहीं था, फिर भी यह आम तौर पर अधिसंख्य निर्दलीय डिप्टियों के साथ था। इनकी किसी विशेष कार्यक्रम अथवा गुट के साथ कोई प्रतिबद्धता नहीं थी और इन्हें 'मारे' या पलें कहा जाता था, और वे केंद्रीय दल में थे। जीरोंदियों (पूर्व ब्रीसोवादियों) का नेतृत्व वेरन्यो, ब्रीसो तथा गूआदे के हाथों में था। ये लोग हालांकि बहुमत में नहीं थे, फिर भी प्रायः वे वोटिंग के संतुलन को नियंत्रित करते थे और अधिकांश मंत्री भी उपलब्ध कराते थे। तीसरा महत्वपूर्ण गुट अथवा दल जैकबिन या मानतनायदों (पहाड़ियों) का था। असेम्बली में ऊपर की सीटों पर बैठने के कारण इनका नाम पड़ा था। इनका नेतृत्व रॉबेसप्यार, मारा, और दातौं जैसी अति महत्वपूर्ण हस्तियों के पास था।

जीरोंदियों और मानतनयादों के बीच चले राजनीतिक संघर्ष ने कनवेंशन को छिन्न–भिन्न किर दिया और यह झगड़ा तभी खत्म हुआ जब पेरिस के आम जन के आक्रमण ने जीरोंदियों को निकाल बाहर किया। यह संघर्ष किस प्रकार का था, इस बात को लेकर अलग–अलग मत हैं। क्या इसका आधार व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता और सत्ता की भूख थी अथवा यह सामाजिक तथा आर्थिक वर्ग संघर्ष का प्रतिबिंब था ? कुछ लेखक जीरोंदी को एक सुगठित दल मानते हैं तो कुछ अन्य जीरोंदी दल के विचार को मानतनयादों के प्रचार का परिणाम समझते हैं। मानतनयादों स्वयं भी सुसंगठित थे और उनके तौर–तरीकों को प्रायः जैकबिन क्लबों में अंतिम रूप दिया जाता था, जिनकी लगाम पूरे तौर पर उन्हीं के हाथों में थी। जीरोंदी को उच्च बुर्जुआ वर्ग का प्रतिनधित्व करने वाले धनिक दल के रूप में देखा जाता है, जबकि मानतनयादौं का आधार निम्न मध्यम वर्ग तथा जन साधारण में था। मानतनयादों ने जनता की जरूरतों से जुड़ी नीतियों को अपनाया और जन समर्थन मांगने तथा जनता की मांगों को पूरा करने वाली नीतियों को अपनाने में भी कभी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। विदेशी युद्ध का खराब संचालन, और फांस के अन्दर क्रांतिकारी कागजी मुद्रा 'आसीन्या' का अवमूल्यन जैसी भीषण आर्थिक समस्याएं तथा असमाधेय खाद्य समस्या कुछ ऐसे तत्व थे जो जीरोंदियों की स्थिति को कमजोर कर रहे थे। इसके बजाय उन्होंने प्रति–क्रांति तथा प्रवासियों के विरूद्ध कानूनों पर अपना ध्यान लगाया। जीरोंदियों को निर्णायक झटका पेरिस ने क्रांतिकारी उग्र गुटों (सां कूलॉत) की ओर से लगा। सां–कूलॉत ने कनवेंशन पर हमला कर दिया और 2 जून, 1793 को मानतनयादों को सत्तारूढ़ कर दिया। इस तरह, तख्ता पलटने का काम संख्या में कम मानतनयादों तथा सां–कूलॉत के मिले–जुले बल ने किया।

जैकबिनों ने अक्टूबर 1793 में एक अन्तरिम क्रांतिकारी सरकार बना दी जिसकी परिणति वास्तविक तानाशाही तथा 'आतंक' में हुई। इस सरकार में लोकतांत्रिक तथा अत्याचारी प्रवृत्तियों के जटिल मिश्रण के संकेत थे। 'आतंक' काल की विभिन्न ज्यादतियों के परिणामस्वरूप जैकबिन गणतंत्र के विरूद्ध प्रतिक्रिया हो गई। 27 जुलाई, 1794 को रॉबेसप्यार के नेतृत्व में मानतनयादों का रूढ़िवादियों ने सफाया कर दिया। इन रूढ़िवादियों ने इसके लिए उग्र सुधारवादी क्रांति की ज्यादतियों को ही हथियार बनाया।

वर्ष 1795 से केंद्रीय भूमिका में 'मारे', पूर्ववर्त्ती काल के निर्दलीय अथवा केंद्रीय दल आ गया। इसमें सुधरे जीरोंदी, पछताए मानतनयादों, अति उत्साही गणतंत्रवादी, यहां तक कि समर्पित कैथोलिक भी शामिल थे। इसके सदस्य अधिकतर भूतपूर्व अमीर तथा बुर्जुआ वर्ग के वे लोग थे जिनकी दिलचस्पी

किसी विचारधारा में इतनी नहीं थी जितनी की अपनी जायदाद को बढ़ाने में। 'सां–कूलांत' निहत्थे हो चुके थे और वामपंथी गुटों का ध्वंस हो चुका था। फांसीसी क्रांति का अंतिम प्रमुख प्रकरण था 1796 का बावफ षडयंत्र, जिसके माध्यम से संपत्ति वितरण के क्रांतिकारी वामपंथी विचारों और साम्यवादी (कम्युनिस्ट) आदर्शवाद के एक प्रारंभिक स्वरूप को लागू करने की कोशिश की गई थी। बावफ और उसके सहयोगियों को पकड़ लिया गया और अत्यंत बेरहमी से उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। दलीय आंदोलन 1815 में संविधानसम्मत राजतंत्र की बहाली तक यथार्थ में निलंबित रहा, और तभी तीन प्रमुख दलों के विभाजन भी फिर उभर का सामने आ गए।

बोध प्रश्न 3

1) गणतंत्रवाद के विचारों को प्रचारित करने में राजनीतिक क्लबों तथा समितियों की क्या भूमिका रही ? 100 शब्दों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

2) फॉयां पार्टी के मुख्य विचार क्या थे ? 50 शब्दों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

3) जरोंदी दल के अनुयायियों तथा मानतनयादों के बीच प्रतिद्वंद्विता के मुख्य तत्व क्या थे ? 50 शब्दों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

4.5 सारांश

इस इकाई में हमने गांवों तथा कसबों के आम लोगों पर आर्थिक संकट के प्रभाव का अध्ययन किया। यह स्पष्ट है कि राज्य की आर्थिक कठिनाइयों ने सामाजिक तथा राजनीतिक संकट को जन्म दिया, जिसकी परिणति फांसीसी क्रांति में हुई। आपने क्रांति की शब्दावली तथा विचारधारा प्रदान करने में दार्शनिकों की भूमिका पर भी ध्यान दिया होगा। हमने यह भी पढ़ा कि कैसे तृतीय इस्टेट सम्राट की प्रजा नहीं अपितु फ्रांस के नागरिकों का प्रतिनधित्व करने वाली राष्ट्रीय असेम्बली बन गई। इससे वैधता के नए सिद्धांत स्थापित हुए जिन्होंने निरंकुशवादी शासन के सामंती ढांचे का स्थान ले लिया। हमने यह भी विश्लेषण किया कि वैधता के सिद्धांत कैसे क्रांति की प्रकृति बदलने के साथ स्वयं भी बदलते रहे। आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि क्रांतिकारी राजनीति ने किस प्रकार राजनीतिक दलों तथा राजनीतिक विचारधाराओं को जन्म दिया।

4.6 शब्दावली

प्राचीन शासन : फ्रांस में उस जीवन शैली तथा सरकार के लिए 1790 के दशक में खोजा गया शब्द, जिसे क्रांति ने 1789 में नष्ट कर दिया था।

कायें : शिकायतों के रजिस्टर जिन्हें तीनों इस्टेट ने बनाया था।

प्रवासी : वे लोग जो फ्रांस से चले गए थे और विदेशी ताकतों पर इस बात के लिए दबाव डाल रहे थे कि वे क्रांति का दमन करें।

इस्टेट : (तीन) वर्ग जिनमें फ्रांस का समाज बंटा हुआ था – पुरोहित वर्ग, अमीर जन और आम लोग।

गुइलोटिन : फांसी देने के लिए प्रयुक्त एक भारी तिरछा धारदार हथियार, जो बहुत ऊंचाई से अपराधी की गरदन पर गिराया जाता था जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो जाता था।

दशमांश . शाब्दिक अर्थ – दसवां हिस्सा। यह एक कर होता था जिसे गेहूं, जौ तथा राई जैसी प्रमुख फसलों पर लगाया जाता। यह कर धर्मसंस्था (चर्च) लेती थी।

4.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) देखिए उपभाग 4.2.1
2) सरकारी व्यय में कटौती में विफलता, दोषपूर्ण कर प्रणाली, अमीर जन को वित्तीय छूट, आदि। देखिए उपभाग 4.2.2
3) देखिए उपभाग 4.2.5

बोध प्रश्न 2

1) सामंती विशेषाधिकारों की समाप्ति, समानता तथा न्याय की स्थापना, मनुष्य के अधिकारों की घोषणा, आदि। देखिए भाग 4.3
2) देखिए उपभाग 4.3.2

बोध प्रश्न 3

1) देखिए भाग 4.4
2) देखिए उपभाग 4.4.1
3) देखिए उपभाग 4.4.2